due to sluggish capital market conditions.

* On the external side, the export growth has been sluggish which has been aggravated by fall in world export growth. Export growth at (–) 2.88% has shown a substantial decline during April—December 1998.

* Demand constraints constitute one of the important reasons for decline in industrial growth. while there has been decline in growth in textiles on account of slowdown in consumption demand, cement and steel have been affected by lack of investment demand.

* Indian corporates have also been affected by competition from cheap imports, owing to devaluation on currencies in East Asia and Brazil.

(c) No annual target of industrial growth for the year 1998-99 has been fixed. However, the Government has announced various measures for correcting sectoral policies and to induce faster growth. In the Budget for 1999-2000, various measures have been announced for revival of industry to accelerate industrial growth. These measures are likely to lead to a favourable impact on industrial growth.

Central investment subsidy for North-Eastern States

2050. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the category in which Central investment subsidy in industries has been given to the North-Eastern States;

(b) the rate of subsidy alongwith the total amount of capital investment given to this North-Eastern Region;

(c) whether the area can be called "No industries region"; and

(d) if so, what steps have been taken in this regard?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) All industrial units other than those run departmentally and located in the notified backward areas were eligible for subsidy under the Central Investment subsidy scheme. The backward areas were classified into three cateogories viz. category 'A' Category 'B' and Category 'C'. The rate of subsidy was ranging between 10%—25% of the fixed capital investment, subject to a ceiling of Rs. 25 lakhs. Since inception of the Scheme till date, an amount of Rs. 77.75 crores has been released to the North-Eastern States.

(c) and (d) All the States in the North-Eastern Region were notified as industrially backward areas and were included in Category 'A' which covered the areas of 'No Industry Districts' and 'Special Region Districts.'

A new Industrial Policy for the North-Eastern Region providing a number of incentives and other fiscal benefits was announced in December, 1997 for accelerating industrial development of the region.

Sale tax exemption to Tata Indica Car Manufacturers

2051. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the Maharashtra Government have exempted Tata Indica Car manufacturers/traders from paying Sales tax thereon;

(b) if so, whether his Ministry has ensured that the fruits of exemption reach the consumer who are the targeted beneficiaries; and

(c) if so, how and if not, why?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) At present there is no information of Maharashtra Government's having exempted Tata Indica Car from sales tax.

(b) and (c) Do not arise. However, it may be stated that there is no price regulation or control in the Automotive sector.

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना

2052. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ ऐसे उपक्रम हैं, जिनके कर्मचारियों को बहुत दिनों से वेतन नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एक निश्चित समय-सीमा के भीतर उपर्युक्त कर्मचारियों को वेतनों का भुगतान करने के लिए कदम उठाने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछ रूग्ण उपक्रमों में मजूरी की अदायगी की राशि बकाया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले कुछ मंत्रालयों से प्राप्त अनन्तिम सूचना के आधार पर सितम्बर, 1998 को समाप्त तिमाही को मजूरी तथा वेतन के कारण कुल बकाया देनदारी लगभग 100 करोड़ रुपए है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को केन्द्रीय बजट 1999-2000 में आयोजना भिन्न ऋणों के लिएं 1735 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जोकि मुख्यतः रूग्ण तथा सुधार कर रहे उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन तथा मजूरी की अदायगी के लिए है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से रोजगार

2053. **प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से अनेक लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से कितने लोग लाभान्वित हुए और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस उद्योग के माध्यम से और रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (घ) जी, हां। वर्ष 1997-98 तक खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 56.50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है जिसमें खादी के अन्तर्गत 14.01 लाख तथा ग्रामोद्योग के अन्तर्गत 42.49 लाख व्यक्ति हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की पूरी संभाव्ता का उपयोग करने के लिए, 2 मिलियन व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार सृजित करने के लक्ष्य सहित, वर्ष 1995-96 में एक नये कार्यक्रम नामतः ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। पिछले तीन वर्षों के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग के माध्यम से लाभान्वित राज्यवार व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योग के अन्तर्गत राज्यवार रोजगार 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98

(रोजगार लाख व्यक्ति)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
	राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.53	3.59	3.60
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	0.01